है या नहीं ? यदि नहीं तो क्या आप इस पर विचार करेंगे ?

SHRI CHARANJIT CHANANA: I have just now informed the hon. Members that the State Mineral Development Corporation is conducting a feasibility survey into the utilisation of the mineral resources of the State, including granite. As soon as the State Government finalise the feasibility studies, then they would think of setting up plants. I may state for the information of the House that since Rajasthan has industrially backward areas, we are having a meeting in Jaipur on the 3rd and 4th to consider this question.

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के जवाब देने के पहले मैं कहना चाहता हूं कि यह मेरा आरोप है कि आज के लिए मैंने 9 क्वेश्चन दिए थे और उन 9 में से सब से अनइम्पार्टेंट क्वश्चन को लाया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : आपको मैंने जवाब दे दिया है ।

श्री राम विलास पासवान : **

MR. SPEAKER: Not allowed.

श्री राम विलास पासवान :**

MR. SPEAKER: Nothing will go on record.

दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते का भुगतान

*443. श्री राम विलास पासवान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को 1 नवम्बर, 1973 से 31 जनवरी, 1978 तक की अवधि के लिए बढ़ी हुई दर से मकान किराया भत्ते का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो और आसूचना ब्यूरो के कर्मचारियों को इस भत्ते का भुगतान कर दिया गया है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) to (c). The whole question of the date from and rate at which house rent allowance is admissible is under consideration.

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं और जो मेरे सेन्टीमेंट्स हैं उनको नोट कर लीजिए । मेरे जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे वे इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे । मैंने जो क्वेश्चन किया था उसके फर्स्ट पार्ट का तो जवाब दिया ही नहीं गया है । मेरे प्रश्न का भाग (क) है—

"क्या दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को 1 नवंबर, 1973 से 31 जनवरी, 1978 तक की अवधि के लिए बढ़ी हुई दर से मकान किराया भत्ते का अभी भुगतान किया गया है या नहीं ।"

आपने कह दिया कि उसका हम पता लगा रहे हैं कि किस डेट से दिया जाए ।

मेरा थर्ड क्वेश्चन था कि—

"क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो और आसूचना ब्यूरो के कर्मचारियों को इस भत्ते का भुगतान कर दिया गया है ।"

उसका आपने कहीं जवाब ही नहीं दिया है । तो इसका पहले जवाब दे दें तब न पूरक शुरू करूं ।

**Not recorded.

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने तीनों का जवाब दिया है । मैंने कहा है कि यह सरकार के पास विचाराधीन है कि किस तारीख से और किस रेट से देना है । तीनों का यही जवाब है ।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: This is no answer. He has to say 'yes' or 'no' according to (a), (b) and (c). How can he give the answers together? (*interruptions*). The point is: Is the answer to (a) 'yes' or 'no'? Is the answer to (b) 'yes' or 'no'? Is the answer to (c) 'Yes' or 'no'. This is what we want to know.

श्री राम विलास पासवान : मेरा पूरा जवाब आ जाए तब तो प्रश्न पूछूं ।

अध्यक्ष महोदय : जवाब आ गया है न ।

श्री राम विलास पासवान : आप प्रश्न देख लीजिए, उसमें एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, ए० बी० सी० अलग-अलग प्रश्न हैं । ....(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : तीसरे के बारे में पूछ रहे हैं ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने कहा कि तीसरे के बारे में भी वे हां या ना में जवाब चाहते हैं तो मैंने कहा है कि यह सरकार के विचाराधीन है कि सी०बी० आई० और आई०बी० को किस डेट से देना है यह अभी तय नहीं किया है, यह विचाराधीन है, हमारे कंसीडरेशन में है ।

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: He will inform you.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Could you please explain to me if the answer to (c) is 'yes' or 'no' ?

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने यह पूछा है कि कोई पे किया भी है या नहीं ?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: How can I say 'yes' or 'no' ? I will explain it now. Please hear me. (*Interruptions*). I am not going to say 'yes' or 'no'. (*Interruptions*). I will explain to the House that we have to consult the Finance Ministry in this matter. First, the Finance Ministry gave effect to it from a certain date and then, again they said 'No, it should be from this date.' So, now it is under correspondence with the Finance Ministry and till the date is not decided, how can I say that it is given? It is given, but from a certain date.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: What date?

MR. SPEAKER: Something he has said. It has been said that it has not been finalised up to what date and how much.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : The difficulty is, the date must be known.

MR. SPEAKER: That is what he said. After finalisation of the date he will inform you.

PROF. MADHU DANDAVATE: His reply is neither 'yes' nor 'no'.

श्री दौलतराम सारण : दिया है या नहीं दिया है, हां या ना में उत्तर दें ।

MR. SPEAKER: After finalisation of the date, he will inform.

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न है कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि पुलिस आवास की कमी है और यदि पुलिस आवास की कमी है तो कितने प्रतिशत आपके यहां ऐसे पुलिस कर्मचारी हैं जिनको आपने हाउस दिया है, घर दिया है और कितने ऐसे हैं जिनको घर नहीं दिया है, जिनको घर नहीं दिया है, उनके लिए आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : आज 35 प्रतिशत को दिया गया है और जिनको नहीं दिया गया है, उनके बारे में थर्ड पे कमीशन में कहा गया है कि हाउस रेंट के अलावा भी उनको कंपंसेशन देंगे, अभी डेट तय नहीं की गई है, क्योंकि—

श्री राम विलास पासवान : मेरा दूसरा प्रश्न है.

अध्यक्ष महोदय : अभी दूसरा है ?

श्री रामविलास पासवान : पहले तो क्लोरिफिकेशन पूछा था कि जवाब क्यों नहीं दिया । मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि नेशनल पुलिस कमीशन ने रिपोर्ट दी है । आज जो पूरे देश में पुलिस आन्दोलन जोर पकड़ रहा है और उनके मन में आक्रोश है तो क्या सरकार जो नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट है, उसने जो सुझाव दिए हैं उन पर सरकार अमल करने जा रही है और यदि जा रही है तो कब तक ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : कमिशन की रिपोर्ट का सरकार अध्ययन कर रही है।

SHRI MANORANJAN BHAKTA: Sir, the police officers of both Delhi and Andaman and Nicobar Islands have a common cadre in the Dani Police Service. So, I would like to ask the Minister, what action he has taken in respect of police officers working in the remote territories of Andaman and Nicobar Islands where for months together they could not get the rations and other facilities and are working in adverse conditions. I would also like to know whether the Minister has received any proposal from the Andaman and Nicobar Administration to this effect and if so, what action he has taken so far and if not, what action he is likely to take.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, the question is limited. The question is regarding the house rent allowance and compensation given in lieu of the accommodation which is not given to the particular officers.

So far as Andaman and Nicobar Islands are concerned, free barrack accommodation for unmarried and free unfurnished accommodation for married or house rent allowance at the rate of 7-1/2 per cent of pay per month for Group 'C' personnel, for those personnel who are keeping families with them, is given.

श्री रामावतार शास्त्री : क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस के लोगों ने मकान भत्ता या दूसरे सवालों को ले कर दिल्ली में आन्दोलन चलाने के लिए आपको सूचना दी है और अगर दी है तो....

अध्यक्ष महोदय : नहीं दी है तो क्यों नहीं दी है ?

श्री रामावतार शास्त्री : क्यों नहीं दी है इसका जवाब यह है कि हम लोग दिलवा देंगे ।

अगर कोई इस तरह की बात उनके यहां चल रही हैं तो क्या कोई आन्दोलन शुरू होने के पहले आप उनके संगठनों से बातचीत करके कोई रास्ता निकालने का विचार रखते हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : जरूर रखते हैं ?

SHRI M. M. LAWRENCE: Will the Government consider giving a special allowance for the Delhi Police to act quickly? I am asking this question because on the day of the National Integration Council meeting, the Chief Minister of Kerala was gharaoed, not gharaoed actually, but he was physically attacked by RSS people.

MR. SPEAKER: Does it arise out of this question?

SHRI M. M. LAWRENCE: The police was informed immediately, but only after 45 minutes the police came on the spot. To avoid such a situation, will the Government consider to give a special allowance to the Delhi Police so that they can act quickly, impartially and without fear?

MR. SPEAKER: No, it does not arise.

Setting up of Public Sector Industries in Punjab

*444. SHRI R. L. BHATIA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Punjab State has not been allocated any medium or large industry so far ;

(b) whether Punjab has been neglected by the Union Government in the setting up of public sector industries in the State over the years ;